87 फीसद क्षेत्र यानी कुल 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर के पाकिस्तान के इलाके पर पैनी नजर रखने में सक्षम हो गया है भारत अपने निगरानी उपग्रहों के जरिये।

आजकल

मजबूत होगी सरहदों की अंतरिक्ष से निगहबानी

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

बेशक कार्टोसैट सीरीज के नए उपग्रह के प्रक्षेपण की कामयाबी का महत्व इसरो से ज्यादा देश के लिए है जिसे आस-पड़ोस से आतंकी घुसपैठ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यह मामला असल में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस की वह व्यवस्था बनाने का है जिसमें सरहदों की निगरानी सुदूर अंतरिक्ष से की जा सकती है। जब देश एक बार कार्टोसैट और इस जैसे निगरानी उपग्रहों की पूरी श्रृंखला अंतरिक्ष में तैनात कर देगा, तब कहा जा सकेगा कि बुरे इरादों वाले पड़ोसी मुल्कों से किसी भी आतंकी का हमारी धरती पर आना नामुमकिन हो जाएगा और ऐसे में आतंक की वह विषबेल स्वत : ही सूख जाएगी

प्रतीकात्मक

हाल में (27 नवंबर, 2019 को) इसरो ने अंतरिक्ष से धरती के चप्पे-चप्पे की निगरानी के लिए अपने प्रतिष्ठित रॉकेट पीएसएलवी-सी47 से कार्टोसैट-3 नामक सेटेलाइट को उसकी कक्षा (ऑर्बिट) में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। कार्टोसैट सीरीज का यह नौंवा उपग्रह है। कार्टोसैट सीरीज की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी, लेकिन सैन्य महत्व के उपग्रहों के सिलसिले की बात करें तो इसका आरंभ वर्ष 2007 में कार्टोसैट-2ए के प्रक्षेपण से हुआ था। यह दोहरे उपयोग वाला उपग्रह था जो मौसम की जानकारियां बटोरने के साथ भारत के अड़ोस-पड़ोस में मिसाइलों की हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। इसके बाद जून 2012 में छोड़े गए कार्टोसैट-2सी से पड़ोसी देशों के संवेदनशील ठिकानों के वीडियो रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण कर उन्हें वापस धरती पर भेजने की सुविधा देश को मिल गई। इसी सीरीज में अगला उपग्रह कार्टोसैट-2ई था जो जून 2017 में छोड़ा गया।

बेशक कार्टोसैट सीरीज के नए उपग्रह के प्रक्षेपण की कामयाबी का महत्व इसरो से ज्यादा देश के लिए है जिसे आस-पड़ोस से आतंकी घुसपैठ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यह मामला असल में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस की वह व्यवस्था बनाने का है जिसमें जमीनी सरहदों की निगरानी सुदूर अंतरिक्ष से की जा सकती है। जब देश एक बार कार्टोसैट और इस जैसे निगरानी उपग्रहों की पूरी श्रृंखला अंतरिक्ष में तैनात कर देगा, तब कहा जा सकेगा कि बुरे इरादों वाले पड़ोसी देशों से किसी भी आतंकी का हमारी जमीन पर आना नामुमकिन हो जाएगा और ऐसे में आतंक की वह विषबेल स्वतः ही सूख जाएगी, जिसे छद्म युद्ध की नीति के तहत शत्रु देश पालते-पोसते आए हैं। पांच साल के जीवनकाल वाला कार्टोसैट-3 तीसरी पीढ़ी का बेहद चुस्त और उन्नत उपग्रह है जिसमें हाई रिजॉल्यूशन तस्वीर लेने की क्षमता है। इसका भार 1,625 किलोग्राम है और यह बड़े पैमाने पर शहरों की प्लानिंग, ग्रामीण संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास, तटीय जमीन के इस्तेमाल और जमीन के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस तकनीक से लैस यह सेटेलाइट धरती के किसी भी इलाके का इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाप सकेगा। इस खूबी से यह सेटेलाइट सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए जमीन पर कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सिग्नल पकड़ सकेगा। यह तकनीक दुश्मन देश के रडार को ढूंढने में मददगार होगी। इस तरह यह सेटेलाइट भारत के जंगी विमानों को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की निगाह में आने से बचा सकेगा। इन्हीं खूबियों के चलते कार्टोसैट-3 को भारत की आंख भी कहा जा रहा है।

अभी जारी है सिलसिला : कार्टोसैट-3 के प्रक्षेपण के साथ ही इसरो ने सीमाई इलाकों की निगरानी के लिए जल्द ही एक और सेटेलाइट छोड़ने का एलान किया है। इसरो की योजना के मुताबिक आगामी 11 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी-सी48 रॉकेट की मदद से रीसैट-2बीआर1 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा जो इस (रीसैट) श्रृंखला का दूसरा सेटेलाइट होगा। इस सीरीज में इस साल 22 मई को रीसैट सीरीज का पहला उपग्रह छोड़ा गया था। इस श्रृंखला में 4 से 5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाना है, ताकि सरहदी इलाकों की रोजाना निगरानी हो सके। उल्लेखनीय है कि उड़ी हमले के बाद सितंबर, 2016 में जब भारतीय सेना ने विख्यात सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था तो उसमें एक अहम रोल कार्टोसैट सीरीज के उपग्रहों ने भी निभाया था। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इन उपग्रहों से लिए गए उच्च गुणवत्ता के फोटो उपलब्ध कराए थे, जिनके विश्लेषण के बाद सेना को जमीनी हालात का आकलन करने और हमले की सर्वाधिक उपयुक्त जगह एवं समय का चुनाव करने में मदद मिली थी।

बात चाहे कार्टोसैट की हो या रीसैट की, इनमें लगे कुछ खास उपकरण अंतरिक्ष से पृथ्वी के विभिन्न इलाकों की बेहद बारीकी से फोटो लेना मुमकिन बनाते हैं। सर्विलांस सेटेलाइट कहलाने वाले इन उपग्रहों में एक विशेष एक्स-बैंड सिंथेटिक अपरचर रडार लगा होता है। यह रडार असल में इजरायली सिस्टम टेकसार-1 का संशोधित और देसी विकल्प है जिससे एक बार में धरती के 5 से 10 किलोमीटर के इलाके में मौजूद वस्तुओं की पहचान की जा सकती है। इतनी सूक्ष्मता से मिलने वाली जानकारी का अर्थ यह है कि दुश्मन देश की सैन्य हलचलों से लेकर आतंकियों की हर गतिविधि का समय रहते पता लग सकता है।

भारत के आंख-कान : शत्रु को परास्त करने का एक आसान तरीका यह है कि उसकी तैयारियों और उसके मंसूबों का पहले से अंदाजा लगा लेना। प्राचीन समय से ही कई युद्ध इसी कौशल से जीते गए हैं। हालांकि तब ऐसे काम गुप्तचर किया करते थे। गुप्तचरों और खुफिया एजेंसियों की भूमिका अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि दुश्मन देशों में हमारे खिलाफ हो रही गतिविधियों की टोह लेना आसान नहीं रह गया है। रणनीतिक स्तर पर शत्रु देशों की तैयारियों का पता लगाने का काम हालांकि अब भी खुफिया तंत्र को ही करना पड़ता है, लेकिन टेरर कैंपों की हलचलों और युद्धक तैयारियों का एक ठोस आकलन आसमानी निगरानी से हो सकता है। यह काम सिर्फ विमानों और ड्रोन्स के जरिये संभव नहीं है, क्योंकि वे आसानी से शत्रु देश की निगाह में आ जाते हैं और पकड़ में आने पर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ऐसे में एक ही सूरत बचती है कि दुश्मन इलाकों पर अंतरिक्ष से नजर रखी जाए। इसके लिए इसरो ने पिछले कुछ अरसे में अंतरिक्ष में तमाम निगरानी उपग्रहों की जिस तरह तैनाती की है, वे असल में भारत के आंख-कान बन गए हैं। अक्सर दो देशों के बीच सैन्य संतुलन का आकलन करते समय सैनिकों की तादाद, जंगी जहाजों, विमानों, मिसाइलों और टैंकों आदि की गणना ही होती है, उनमें अंतरिक्ष में तैनात सर्विलांस सेटेलाइटों की गिनती नहीं होती है, लेकिन भारत के अगल-बगल शत्रु इरादों वाले पड़ोसियों की मौजूदगी के मद्देनजर ऐसे उपग्रहों की कीमत किसी भी सैन्य साजोसामान से ज्यादा ही ठहरेगी।

पूरे पाकिस्तान पर निगाह : अगर पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से भारत पर हमले की सिर्फ बंदरघुड़की देने और छद्म युद्ध छेड़ने तक ही सीमित होकर रह गया है तो इसके पीछे एक अहम तथ्य यह है कि भारत अपने निगरानी उपग्रहों के जरिये पाकिस्तान के 87 फीसद क्षेत्र यानी कुल 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर पैनी नजर रखने में सक्षम हो गया है। इससे भारत जब चाहे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सामरिक इलाकों की गतिविधियों को देख सकता है और अपने उपग्रहों के जरिये महत्वपूर्ण नक्शे और तस्वीरें हासिल कर सकता है।

सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पिछले पांच-छह वर्षों में इसरो ने कई ऐसे सेटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं, जिनकी मदद से भारत की क्षमता आस-पड़ोस के 14 देशों के करीब साढ़े 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर दायरे वाले भूभाग पर सूक्ष्म नजर रखने की बन चुकी है। खुद सेना यह स्वीकार करती है कि देश की सरहदों से लेकर पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर हो रही गतिविधियों पर करीबी नजर रखने संबंधी जरूरतों का 70 फीसद हिस्सा इसरो के सेटेलाइट पूरा कर देते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वक्त इसरो के कम से कम 10 उपग्रह ऐसे हैं जो देश की सैन्य और खुफिया जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इनमें खास तौर से कार्टोसैट सीरीज, जीसैट-7, जीसैट-7ए, आइआरएनएसएस यानी इंडियन रीजनल नैविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, माइक्रोसैट, आरआइसैट और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यानी हाइसिस सेटेलाइट का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है।

उपग्रह एक फायदे अनेक

कहने को तो इसरो ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर सर्विलांस सेटेलाइट्स की तैनाती अंतरिक्ष में की है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि अलग-अलग किस्म के ये उपग्रह विभिन्न काम में मददगार हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे यदि बात कार्टोसैट सीरीज के उपग्रहों की करें तो शुरुआत में यह दोहरे उपयोग वाला उपग्रह था जो मौसम की जानकारियां बटोरने के साथ भारत के अड़ोस-पड़ोस में मिसाइलों की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। इसके बाद जून 2012 में छोड़े गए कार्टोसैट-2सी से पड़ोसी देशों के संवेदनशील ठिकानों के वीडियो रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण कर उन्हें वापस धरती पर भेजने की सुविधा देश को मिल गई।

इसी सीरीज में अगला उपग्रह कार्टोसैट-2ई था जो जून 2017 में छोड़ा गया। यूं तो कार्टोसैट सीरीज के उपग्रह ही देश की तमाम सैन्य जरूरतों को पूरा कर देते हैं, लेकिन इनके अलावा कई अन्य सेटेलाइट और हैं जिनसे दूसरे किस्म की बेहद जरूरी और संवेदनशील सूचनाएं देश और सेना को मिलती हैं। जैसे-एक जुलाई, 2013 और 12 अप्रैल, 2018 को अंतरिक्ष में भेजे गए आइआरएनएसएस सीरीज के नैविगेशन उपग्रहों से देश की सरहद के 1600 किलोमीटर इलाके की बारीक निगरानी की जाती है और विशेष मिसाइलों की तैनाती और उनके मूवमेंट की थाह इनके जरिये ली जाती है। इसी तरह 30 अगस्त, 2013 को प्रक्षेपित जीसैट-7 से भारतीय नौसेना को अपनी संचार संबंधी जरूरतें और समुद्री सीमा की निगरानी करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है।

इसके बाद 19 दिसंबर, 2018 को अंतरिक्ष में भेजे गए जीसैट-7ए से भारतीय वायुसेना को अपनी संचार संबंधी जरूरतें पूरी करने में बहुत मदद मिली। यह एक बेहद उच्च क्षमता वाला सैन्योपयोगी उपग्रह है जो मिसाइलों और विमानों की हलचलों पर बारीक नजर रखने के साथ-साथ उड़ रहे विमानों के बीच हो रहे संवाद-संचार को पकड़ सकता है और फौरन उसकी जानकारी जमीन पर मौजूद सेंटर को दे सकता है। यह ड्रोन को कंट्रोल करते हुए उन्हें दुश्मन के इलाके में हमले के लिए भेज सकता है और दुश्मन के ड्रोन पर नजर भी रख सकता है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेटेलाइट यानी हाइसिस को 28 नवंबर, 2018 को छोड़ा गया था और इससे रात के अंधेरे में भी तस्वीरें खींचकर जमीन के कुछ सेंटीमीटर जितने हिस्से की सूक्ष्म निगरानी की जाती है। यहां तक कि जमीन में दबाई गई बारूदी सुरंगों और आइईडी का भी हाइसिस से पता लगाया जा सकता है।

इनके अलावा इसी साल 23 जनवरी, 2019 को प्रक्षेपित उपग्रह माइक्रोसैट-आर को इस मायने में खास कहा जा सकता है कि इसका निर्माण विशुद्ध रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए डीआरडीओ ने किया है। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है यानी इससे जमीनी हलचलों की बेहद सूक्ष्म जानकारी ली जा सकती है। रात में जमीन की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें खींचने में सक्षम यह उपग्रह सेना को हालात के मुताबिक योजना बनाने और दुश्मन की गतिविधि की निगरानी करने में सहयोग करता है।

खरी-खरी

राजनीति की पिच पर ब्रेक डांस!

डॉ. अतुल चतुर्वेदी

राजनीति का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि वहां कोई सिद्धांत नहीं। फिर भी कुछ घाघ नेताओं और घिसे हुए अनुभवी दलों के कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे सबसे पहला तो यही कि कोई रिश्ता इतना अहम नहीं होता जितनी कि सत्ता। सत्ता प्राप्ति के लिए सारे रिश्तों, सिद्धांतों और विचारों की बलि कभी भी दी जा सकती है। रातोंरात धर्मनिरपेक्ष हुआ जा सकता है और घोर सांप्रदायिक या जनवादी भी। राजनीति ये सब परहेज नहीं करती। यहां जातिवाद है भी, नहीं भी। धार्मिक भेदभाव की चीनी दीवारें हैं भी, नहीं भी। क्षेत्रवाद के घुमावदार संकरे दरवाजे हैं भी, नहीं भी।

राजनीति खेल ही है नितांत अनिश्चितताओं का। इस मामले में आज के राजनेता और दल क्रिकेट को भी चुनौती देने में लगे हुए हैं। वहां भी कुछ नियम हैं, अंपायर हैं और हजारों दर्शक हैं, लेकिन राजनीति में अंपायर स्वयं मिल जाते हैं मौका देखकर। दर्शकों अर्थात जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है खिलाड़ियों का। यहां 'सबसे बड़ा खिलाड़ी' की होड़ लगातार जारी रहती है। कोई किसी को भी गुगली खिला देता है। एक से एक फिरकी गेंदबाज भरे हुए हैं। नैतिकता को ताक पर रख वे पिच पर ब्रेक डांस कर रहे हैं और अंग-प्रत्यंग तोड़ने की जगह दूसरों के नर्तक तोड़ रहे हैं।

स्थायित्व और संविधान देश में ऐसी दो चिड़ियाएं हैं, जिनका हवाला देते हुए आप कभी भी कुछ भी कर गुजर सकते हैं। पद के प्रति मोह और सत्ता के प्रति अनुराग इतना प्रबल है कि राजनीतिक दल बेमेल विवाह से लेकर गंधर्व विवाह तक को तैयार बैठे हैं। ब्रह्म विवाह में उनका कोई विश्वास ही नहीं, वे तो राक्षस विवाह के हिमायती ठहरे। परस्पर अग्नि वर्षा और निंदा के हथगोलों से वे लोकतंत्र की फसल का संहार करने के पुनीत अभियान में मन, कर्म और वचन से लगे हुए हैं। हारे को हरिनाम और जीते हुए को प्रणाम ही उनका फलसफा है।

येन-केन-प्रकारेण सत्ता पाकर आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त होना ही उद्देश्य है। ऐसा लगता है कि जन-प्रतिनिधि खुली मंडी में बैठे हैं। जो जितनी ऊंची जीन्स की बोली लगाए, उठा ले जाए माल को। इस आक्रामक मार्केटिंग से कॉरपोरेट घरानों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। बेकार घाटे और मंदी के दुष्चक्र में उलझे रहते हैं। सत्ता के व्यापार में कभी भी मंदी नहीं आती। संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं बशर्ते आप में लचीलेपन, बेशर्मी, लिजलिजेपन का अपूर्व मेल हो।

ट्वीट-ट्वीट

कुछ लोग अयोध्या मामले को ठंडा ही नहीं होने देना चाहते। जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद ने राम मंदिर मामले में पुनर्विचार याचिका लगाई है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी का यही कहना है कि अदालत जो कहे, लेकिन मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी।
रोहित सरदाना@sardanarohit

अमित शाह जिस राष्ट्रव्यापी एनआरसी की बात कर रहे हैं उनका वह फैसला कुछ वैसा ही साबित होगा जैसा हश्र आर्थिक मोर्चे पर मोदी की नोटबंदी ने किया था।
शेखर गुप्ता@ShekharGupta

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पूर्ववर्ती देवेंद्र फड़नवीस की बुलेट ट्रेन समेत तमाम योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। यह दुखद जरूर, लेकिन कड़वी हकीकत है कि प्रत्येक राज्य में बनने वाली नई सरकार यही मानती है कि ज्यादा से ज्यादा रकम जुटाने का यही तरीका है कि पिछली सरकारों की परियोजनाओं को बंद करके नई योजनाएं शुरू की जाएं।
डॉ. अरविंद विरमानी@dravirmani

उत्तराखंड डायरी

सहानुभूति की लहर पर सवार भाजपा

कुशल कोठियाल
स्थानीय संपादक, उत्तराखंड

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन से खाली हुई पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर उनकी पत्नी चंद्रा पंत उपचुनाव जीत गई हैं। राजनीतिक क्षेत्र से अलग रह कर शिक्षिका के तौर पर सेवा कर रहीं चंद्रा पंत ने 3267 मतों से विजय हासिल कीं। वह स्वयं इस चुनाव मैदान में पार्टी के भरोसे उतरी थीं एवं पार्टी खुद सहानुभूति लहर पर सवार थी। कांग्रेस में इस हार के बाद भी जीत जैसा उल्लास है। पार्टी के कुछ नेता तो इसे भाजपा की जीत कहने से भी गुरेज कर रहे हैं। बकौल कांग्रेसी नेता भले भाजपा सहानुभूति लहर पर सवार हो कर सीट बचा ले गई, लेकिन यदि कांग्रेस गंभीरता से उपचुनाव लड़ती और इस सीट से पूर्व में विधायक रहे मयूख महर मैदान में उतरते तो परिणाम कुछ और होता। खैर जीत तो जीत होती है, लेकिन भाजपा सरकार को मतदाताओं ने कुछ संकेत भी दिए हैं, जिन्हें समझने की जरूरत है।

भाजपा ने रुड़की नगर निगम के लिए हुए उपचुनाव में बुरी तरह मात खाई है। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। इस परिणाम के साथ ही भाजपा के हाथ से हरिद्वार जिले के दोनों नगर निगम खिसक गए हैं। हालांकि लाज बचाने के लिए भाजपा नेता यह भी कह रहे हैं कि वोट भाजपा को ही पड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण नगर निगम खोने का दर्द पार्टी हाईकमान तक महसूस किया जा रहा है। मेयर पद पर जीतने वाले प्रत्याशी भाजपा के ही बागी हैं। जाहिर है कि हरिद्वार नगर निगम से भी पार्टी, प्रत्याशी चयन में खामी के चलते हाथ धो बैठी थी। इससे कुछ सबक सीखने के बजाय रुड़की में भी यही गलती दोहराई और हार झोली में गिरी। दोनों निगमों में अपने खास लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे बड़े नेताओं के खिलाफ पार्टी में अंदर ही अंदर आवाज उठने लगी है।

श्राइन बोर्ड बनाने का निर्णय : प्रदेश सरकार ने चारधाम सहित राज्य के 51 प्रमुख मंदिरों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने एवं यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर श्रीवैष्णो देवी माता मंदिर की तर्ज पर श्राइनबोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। आगामी चार दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इससे संबंधित विधेयक के पारित होने की संभावना है। प्रस्तावित बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे एवं वरिष्ठ आइएएस इसके सीईओ होंगे। सरकार के इस फैसले से आम जन भले संतुष्ट हों, लेकिन पंडा समाज विरोध में उतर आया है। मंदिरों के प्रबंधन में उनकी निर्णायक भूमिका न रह पाने की आशंका के चलते यह वर्ग आंदोलित है। कांग्रेस नेता भी स्थिति का फायदा उठाने के लिए उनके पीछे आ गए हैं। वर्तमान में मंदिरों एवं यात्रा मार्गों की व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्राइनबोर्ड के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पंडा समाज की प्रतिक्रिया के कारण ही सरकार निर्णय को टाल रही थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड गठन के बावजूद पंडा समाज के पारंपरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

प्रतीकात्मक

कार्बेट में गैंडे तो राजाजी में दिखेंगे वाइल्ड डॉग : पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडा पुनर्वास योजना के परवान चढ़ने से उत्साहित उत्तराखंड भी अपने यहां गैंडों का संसार बसाने की कवायद में जुट गया है। राज्य वन्यजीव बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए शोध के आधार पर तैयार चार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम बंगाल और असम से यहां 10 गैंडे लाए जाएंगे। असल में वन विभाग के अभिलेखों में उल्लेख है कि एक दौर में कार्बेट के इर्द-गिर्द गैंडों की मौजूदगी थी। इसी के दृष्टिगत यहां फिर से इनका संसार बसाने का निश्चय किया गया और इसके लिए कार्बेट टाइगर रिजर्व को भौगोलिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया। महकमे का दावा है कि गैंडों के आने से यहां की जैव विविधता सशक्त होगी और मानव के साथ संघर्ष की संभावना भी शून्य रहेगी। यही नहीं, इससे पर्यटन की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। कार्बेट में गैंडों की भांति राजाजी टाइगर रिजर्व में भी नए जीव यानी वाइल्ड डॉग को लाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव को भी वन्यजीव बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी है। असल में माना जाता है कि वाइल्ड डॉग प्राकृतिक रूप से गुलदारों एवं जंगली सूअरों की संख्या नियंत्रित करने में मददगार साबित होते हैं। राजाजी से लगे क्षेत्रों में भी गुलदार एवं जंगली सूअरों ने नाक में दम किया हुआ है। इसी के दृष्टिगत यहां मध्य प्रदेश से वाइल्ड डॉग लाए जाएंगे।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या बीसीसीआइ अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए?

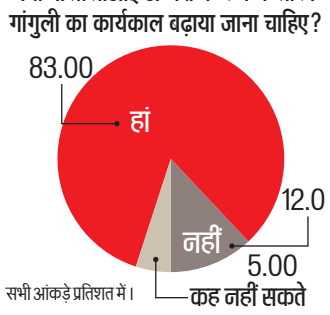

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या उद्धव ठाकरे द्वारा बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा का फैसला सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जैसे मक्खी दूध से हो दी गई निकाल,
हुआ धवन राजीव का कुछ वैसा ही हाल!
कुछ वैसा ही हाल मलाल न करिए भाई,
राम विमुख जो होय न मिलती उसे खुदाई!!
करि प्रभु से विद्रोह सुखी हो कोई कैसे,
रोएगा घर बैठ धवन जी रोएं जैसे।
– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

कितने संवैधानिक हैं हम

गुरु प्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि संकाय, पटना विश्वविद्यालय

जो नागरिक संविधान के प्रति संवेदनशील होगा, वह भारतीय समाज के मुद्दों और चिंताओं के प्रति भी संवेदनशील होगा। साथ ही वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के प्रति भी संवेदनशील होगा

जब भारतीय संविधान की बारीकियों को समझने की बात आती है तो बुद्धिजीवियों और आम जनता के बीच एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। बुद्धिजीवियों को संविधान पर समय-समय पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने की स्वतंत्रता और अवसर मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से यह आम जनता के बीच कभी चर्चा का विषय नहीं बना है। हमें ऐसा लोकतांत्रिक माहौल तैयार करने की जरूरत है ताकि आम लोग भी संविधान से जुड़ सकें। संवैधानिक रूप से संवेदनशील नागरिकों के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए।

जिन लोगों ने संविधान का मसौदा तैयार किया था, वे दूरदर्शी लोग थे। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाया और उनसे निपटने के लिए संविधान में इनबिल्ट मेकेनिज्म रखा। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुविधा देना अनिवार्य है और अभी भी 25 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए यह प्रासंगिक बना हुआ है। राष्ट्र की प्रगति के लिए सामाजिक एकीकरण, सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एक अनिवार्यता है। इसलिए संविधान ने उन लोगों के लिए व्यवस्था की जो जाति-आधारित भेदभाव के कारण पीड़ित थे। देश में दलित नेतृत्व का उदय संविधान से मिले अधिकारों के कारण ही संभव हो पाया है। संविधान ने प्रत्येक भारतीय को हक और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया। इसलिए उन्हें संवैधानिक रूप से संरक्षित नागरिक कहना गलत नहीं होगा।

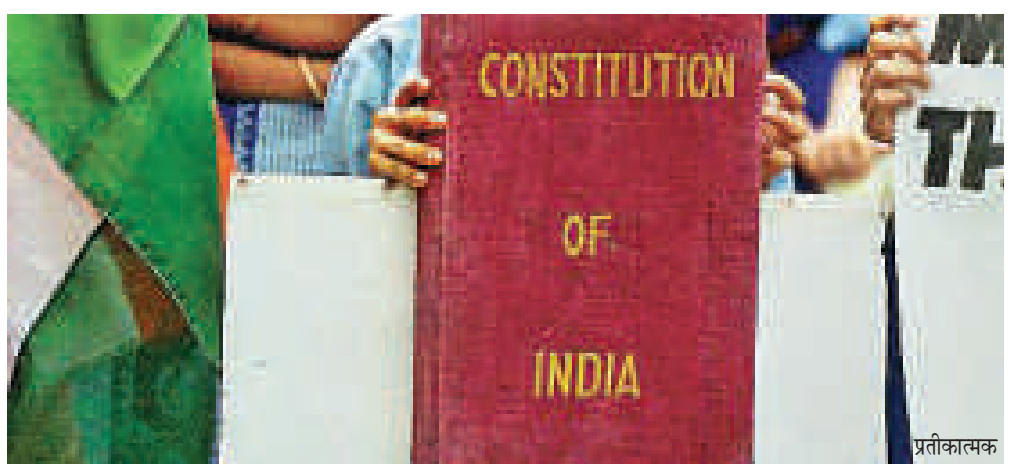

प्रतीकात्मक

प्रासंगिक बने रहने के लिए हर नीति को बदलते समय उसे परिस्थितियों के अनुसार विकसित और अनुकूल करना होता है। ऐसे में आरक्षण को भी उन लोगों के लिए अधिक व्यवस्थित, सुलभ और समावेशी होने के लिए सुधारों की आवश्यकता है, जिनको इसका लाभ नहीं मिला है। सुधार की आवाज समुदाय के भीतर से आनी चाहिए। इसमें वह हिस्सा आता है जहां नागरिक को उदारता दिखाने का अवसर मिलता है। पिछले सात दशकों से हमारे संविधान को लेकर होने वाले संवाद कर्तव्यों से ज्यादा अधिकारों पर केंद्रित रहे हैं।

अब संवैधानिक संवादों को नागरिकों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की ओर मोड़ना जरूरी हो चला है। नागरिकों की समाज, देश और उसके बाद दुनिया के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है। भविष्य में दुनिया नई चुनौतियों का सामना करेगी और एक देश के रूप में भारत को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया आशा और आशावाद के साथ हमारी ओर देख रही है। एक देश के रूप में हमें क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। निरंतर आर्थिक विकास और संपूर्ण लोकतंत्र के साथ हम दुनिया के लिए एक उदाहरण हैं, जो काफी हद तक उपभोक्तावादी, ध्रुवीकृत और हिंसक हो रही है। यह संदेश नीचे तक पहुंचना चाहिए। नए भारत की कहानी का उद्देश्य सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसलिए कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना समय की जरूरत है।

शानदार राजनीतिक विचारक और थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक जॉन राउल्स ने कहा है, 'सामाजिक सहयोग का लाभ और बोझ एक आदर्श समाज में स्पष्ट और उचित रूप से वितरित किया जाना चाहिए।' भारतीय संदर्भ में सामाजिक सहयोग का लाभ लंबे समय तक चर्चा का केंद्रीय विषय रहा है। सामाजिक सहयोग के बोझ को भी स्पष्ट और उचित रूप से वितरित करने की आवश्यकता है। किसी को भी इससे बचना नहीं चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा और दृष्टि का प्रतिनिधि है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान के निर्माताओं के सबसे पोषित सपनों में से एक था। इस सपने को साकार करने के लिए केंद्रीय बिंदु को अब कर्तव्यों में बदलना होगा। स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की राह में कर्तव्य रोड़ा नहीं बनेंगे। कर्तव्य स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ मिलकर काम करेंगे।

हमें याद रखना चाहिए कि संविधान एक विकसित दस्तावेज है। विकास अधिक टिकाऊ और समावेशी हो, इसके लिए हमें अब एक निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। कुशल नागरिकता, जो अपने दृष्टिकोण में कर्तव्यनिष्ठ है, किसी भी समाज या राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है। कर्तव्यपरायण नागरिकों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन भविष्यवादी, पारिस्थितिक रूप से स्थायी और अधिक समावेशी होंगे। मुझे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी द्वारा की गई ऐतिहासिक टिप्पणी याद आती है, 'यह न पूछें कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछें कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं।' आइए हम आत्मनिरीक्षण करें और विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत की यात्रा में योगदान दें।